ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 362-366
I S S N NO.- 2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

भारत में निर्धनता की चुनौतियाँ, समस्या एवं समाधान

डॉ0 ज्योति कुमार पंकज

असि0 प्रो0– अर्थशास्त्र विभाग, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा, सि0 का0 मु0 वि0वि0 दुमका (झारखण्ड), भारत

Received- 17.11.2018, Revised- 19.11.2018, Accepted - 25.11.2018 E-mail: Pankaj_panthi@yahoo.co.in

सारांश : ***भारत वैश्विक स्तर पर उभरती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की जनशक्ति में दूसरा स्थान रखता है। 1991 में किये गये आर्थिक सुधारों से उदारीकरण के चलते भारत विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जहाँ एक तरफ भारत विकास के संदर्भ में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान समय में देश के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या निर्धनता को दूर करने की है। आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। देश में आज भी कुपोषण, अल्प पोषण, शोषण, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार एवं अमीर और गरीब के मध्य बढ़ रही आय की असमानता चिंता का विषय है। अमीर और अमीर हो रहे तथा गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं। ऐसे में तय समय में विकसित अर्थव्यवस्था बनने का सपना अधूरा रह सकता है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफी प्रगति की है परंतु बढ़ती आबादी के चलते जनसामान्य लोगों के उपर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा है। सामान्यतः निर्धनता का अर्थ अभाव की स्थिति से है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तुएँ आर्थिक पिछड़ेपन के कारण नहीं उपलब्ध हो पाती तो वह निर्धन है।***

कुंजीभूत शब्द– निर्धनता रेखा, सामाजिक सूचकां, अपवर्जन, कैलोरी, कुपोषण, आर्थिक पिछड़ेपन आदि।

निर्धनता या गरीबी से आशय समाज की उस परिस्थिति से है जिसमें समाज का एक बहुत बड़ा भाग अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं जिसमें सामाजिक सूचकों में आय एवं उपभोग के निम्न स्तर, निरक्षरता का स्तर, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की कमी, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, चिकित्सीय सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी एवं सामाजिक अपवर्जन सबसे प्रमुख कारण है। निर्धनता रेखा के आकलन का अधार आय या उपभोग स्तरों पर आधारित है इसी को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने निर्धनता रेखा का आधार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 2200 कैलोरी ऊर्जा को प्रतिदिन आवश्यक माना, जिनको प्रतिदिन इतनी कैलोरी नहीं मिल पाती वे गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ–साथ निर्धनता समाप्त हो जाती है परन्तु विकसित देशों में भी निर्धनता के उदाहरण मिलते हैं, जबकि विकसित और अल्पविकसित देशों में निर्धनता की अवधारणा में भारी अंतर पाया जाता है। जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ब्यक्ति की न्यूनतक आवश्यकताएँ निश्चित रूप से एक भारतीय की न्यूनतक आवश्यकताओं से अधिक होगी। अल्पविकसित या विकासशील देशों के लिए व्यापक गरीबी का विद्यमान होना चिन्ता का विषय क्योंकि गरीबी को निर्णय–निर्माण, नागरिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता के अभाव के रूप में भी देखा जाता है। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना और तय समय सीमा में निर्धनता उन्मूलन योजनाओं को पूरा करना शामिल है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के चलते भारत की निर्धनता दर में गिरावट आयी है परन्तु आर्थिक विकास एवं प्रगति होने के बाद भी भारत में निर्धनता को समाप्त करना एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण शहरी विभिन्नता के साथ राज्यों में निर्धनता के स्तर में व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं। इन असमानताओं के चलते निर्धन लोगों के लिए पोषण युक्त भोजन, सुलभ चिकित्सा, बाल श्रम, शोषण, लिंग आधारित भेदभाव, आय की समस्या, जाति व्यवस्था, आवास, शिक्षा एवं रोजगार जैसी समस्याओं का समाधान करना भी एक बड़ी चुनौती है।

अतः एक समय अवधि में निर्धनता की समस्या एवं इससे उत्पन्न चुनातियों का समाधान करना अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। प्रस्तुत आलेख इन्हीं प्रश्नों से जुड़ा है।

अध्ययन का उद्देश्य– भारत में निर्धनता एवं निर्धनता की स्थिति का अध्ययन करना।

निर्धनता की समस्या चुनौतियों एवं समस्या का अध्ययन करना।

निर्धनता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

शोध विधिः– यह शोध पत्र द्वितीयक समंकों पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी शोध पत्र–पत्रिकाएं सरकारी रिपोर्ट एवं पुस्तकों आदि को अध्ययन का आधार

PIF/3.007 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

बनाया गया है।

अध्ययन का क्षेत्रः— अध्ययन के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता की चुनौती, समस्या और समाधान को आधार बनाया गया है।

भारत में निर्धनता का परिदृश्य

वर्ष 1973 से 1993—94 में भारत में गरीबी की व्यापकता के अनुमानः— (प्रतिशत में)

क्षेत्र	1973—74	1977—78	1983—84	1987—88	1993—94
ग्रामीण	56.4	53.1	45.7	39.1	37.3
शहरी	49.0	45.2	40.8	38.2	32.4
सम्पूर्ण देश	54.9	51.3	44.5	38.9	36.0

Source: Plannig commission, Ninth Five year Plan, 1977, 2002, (Delhi 1999) Vol-I Table 1-10, P-28

तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण गरीबी अनुपात जो वर्ष 1973—74 में 56.4 प्रतिशत था वह वर्ष 1993—94 में घटकर 37.3 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में शहरी गरीबी अनुपात 1973—74 में 49 प्रतिशत से घट कर 1993—94 में 32.4 प्रतिशत पर आ गयी। जबकि समग्र गरीबी अनुपात वर्ष 1973—74 में 54.9 प्रतिशत से घटकर 1993—94 में 36.0 प्रतिशत हो गई। स्पष्ट है कि 1977—78 से 1993—94 के 16 वर्षों की अवधि में गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत में भारी कमी हुई परंतु यह कमी डेढ़ दशक से अधिक समय में हुई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 55वें दौर, जुलाई 1999 से जून 2000 तक की अवधि में वर्ष गरीबी का अनुपात वर्ष 1977—78 के 53.1 प्रतिशत से कम होकर 1999—2000 में 26.1 प्रतिशत आ गया।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 61 दौर 2007 के अनुमान वर्ष 2004—05 में निर्धनता रेखा से नीचे की आबादी 23.85 करोड़ थी जबकि इसके पूर्व के वर्ष 1999—2000 में यह संख्या 26.2 प्रतिशत थी। तुलनात्मक रूप से इस अवधि में देखा जाय तो वर्ष 1999—2000 से 2004—05 के दौरान निर्धनों की संख्या में 2.17 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई जबकि इसी अवधि में निर्धनता अनुपात 26.10 से घटकर 21.8 प्रतिशत हो गया।

जुलाई, 2009 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित एन0सी0सक्सेना कमेटी ने माना कि भारत में 50% आबादी गरीब है और सर्वाधिक गरीबों में केवल 49.1 प्रतिशत के पास ही बी0पी0एल एवं अन्त्योदय अन्न योजना का कार्ड है वहीं 17.4 प्रतिशत धनी वर्ग भी ऐसे कार्डधारक बने हुए हैं, जबकि 23 प्रतिशत को बी0पी0एल एवं अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ अभी भी नहीं मिल पाया है।

विकासशील देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का स्तर

निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या (%में)

क्षेत्र	1985	2000
सब—सहारा अफ्रीका	46.8	43.1
पूर्वी एशिया	20.4	4.0
चीन	20.0	2.0
दक्षिण एशिया	50.9	26.0
भारत	55.0	25.4
पूर्वी यूरोप	7.8	7.9
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	19.1	11.4
कुल	32.7	18.0

स्रोत—विश्व विकास रिपोर्ट 2000—01

विकासशील देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति का आकलन किया जाय तो वर्ष 2000 में सहारा अफ्रीका, पूर्वी एशिया, चीन, दक्षिण एशिया, पूर्वी यूरोप एवं लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों की तुलना में जहाँ 1985 में भारत में गरीबी अनुपात 55.0 प्रतिशत था वह घट कर वर्ष 2000 में 25.4 प्रतिशत हो गया परंतु विकासशील देशों के गरीबी अनुपात से अधिक ही रहा।

भारत में गरीबी की माप हेतु गठित समितियाँ

भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं द्वारा समय—समय पर गरीबी के निर्धारण एवं माप हेतु अनेक मापदण्ड बनाये गये, जिसमें वर्ष 1901 में सबसे पहला अनुमान दादाभाई नौरोजी द्वारा "च्वअमतजल दक नदइतपजपेी त्नसम पद प्दकपं" में 1867—68 की कीमतों पर 16—35 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कम आय वाले लोगों को निर्धन माना गया।

National planning committee 1938 में पं0 नेहरू की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर 15—20 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह के नीचे पाने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे माना। जबकि वर्ष 1944 में बनी कमिटी जीम ठवउइंल च्संद ने 75 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष को माना।

योजना आयोग द्वारा गठित Working group 1962 ने भारत में (पहली बार) इस समूह द्वारा स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खाद्य तथा गैर खाद्य के रूप में 20 रूपये तथा 25 रूपये का मापदण्ड निर्धारित किया।

Study by V.M.Dandekar and N.Rath 1971 द्वारा गरीबी के निर्धारण हेतु सबसे पहले उपभोग स्तर का निर्धारण कर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी मापदण्ड को आवश्यक माना। वर्ष 1960—61 की कीमतों पर ग्रामीण परिवारों के लिए 15 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रति माह तथा शहरी परिवारों के लिए 22.50 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया।

Task Force on "Projection of minimum

PIF/3.007 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

Needs and effective consumption Demand" headed by Dr. Y.K.Alagh-1979, यह सरकार द्वारा गठित पहली समिति थी जिसने गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर के रूप में परिभाषित किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2200 किग्रा0 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मापदण्ड निर्धारित किया। समिति ने 1973–74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 49.09 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 56.64 रूपये प्रतिमाह व्यय के निर्धारण को निर्धनता का आधार माना।

Lakdawala Expert Group-1993 : इस समिति ने अलघ समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड को बरकरार रखते हुए उपभोग व्यय की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की और गरीबी रेखा को अलग से परिभाषित नहीं किया।

Tendulkar Expert Committee 2009: योजना आयोग द्वारा वर्ष 2005 में गठित विशेषज्ञ समूह ने शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 32 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 26 रूपये कुल उपभोग व्यय को निर्धनता का आधार माना।

रंगराजन समिति 2014: वर्ष 2012 में गठित रंगराजन समिति ने 2011–12 की कीमतों पर शहरी दैनिक प्रतिव्यक्ति उपभोग 47 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रूपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को निर्धन माना। जबकि संपूर्ण भारत के संदर्भ में 2011–12 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह से कम उपभोग व्यय करने वाले लोगों को निर्धन माना।

प्रो0 अमर्त्य सेन ने अपने लेख ''गरीबी की गहनता'' में गरीबी की माप की एक विधि विकसित की जिसके आधार पर उन्होंने गरीबी गुणांक निकाला और बताया कि यदि किसी देश में गरीबी रेखा का पैमाना 250 रू0 प्रतिमाह है तो इससे कम आय वाले व्यक्ति गरीब हैं परन्तु इस आय रेखा के नीचे भिन्न–भिन्न आय वर्ग के लोग होंगे जैसे–100, 130, 145.... 200. आदि। जो व्यक्ति इस सीमा के जितना नजदीक होगा वह उतना ही कम गरीब होगा और जो इस सीमा से जितना दूर होगा वह अधिक गरीब होगा। इसे सेन का गरीबी गुणांक कहते हैं। उपरोक्त समितियों के द्वारा समय–समय पर निध ार्रित निर्धनता के मापदण्ड एवं अनुमानों में काफी भिन्नता है। जैसे दांडेकर एवं रथ ने माना कि वर्ष 1960–61 में ग्रामीण जनसंख्या का 40 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या की 50 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी।

मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने अपने लेख (Rural poverty and Agriculture performance in India the journal of development studies, 1977) में बताया कि 1956–57 में ग्रामीण जनसंख्या का 54.1% एवं 1960–61 में 38.9% लोग गरीब थे।

छठी पंचवर्षीय आयोग ने माना कि सन् 1972–73% में ग्रामीण जनसंख्या के 54.09% एवं शहरी जनसंख्या के 42. 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे जो 1977–78 में घट कर क्रमशः 51.2% एवं 38.2% हो गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1983–84 में कुल जनसंख्या के 37.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे जबकि सन् 1987–88 में यह ग्रामीण जनसंख्या का 33.3% तथा शहरी जनसंख्या का 20.1% एवं कुल आबादी की गरीबी 29.9% थी।

आर्थिक समीक्षा 2001–02 दिए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1977–78 एवं 1999–2000 के मध्य गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात 51.3% से घट कर 26.1% हो गई और गरीबों की संख्या 328.9 मिलियन से कम होकर 260.3 मिलियन हो गई। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में निर्धनता के मापदण्ड को निर्धारित करना आज भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह निर्धनता सामाजिक, आर्थिक समस्या के साथ संरचनात्मक कारकों से प्रभावित हैय जिसमें आय की असमानता, संसाधनों का असमान वितरण, लिंग असमानता, वर्णव्यवस्था, खराब स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार एवं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जैसे कारक शामिल हैं। देश की आजादी के छः दशक से अधिक समय बीतने तथा वर्ष 1991 में प्रारंभ किये गये आर्थिक सुधारों के बाद भी गरीबी जैसी समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो सका है। 90 के दशक के दौरान निर्धनता पर किये गये अधिकतर अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में गिरावट की कोई विशेष प्रवृति नहीं पायी गई।

भारत में निर्धनता से संबंधित जो भी आकलन किये गये उनमें निर्धनों की संख्या पर ध्यान दिया गया जबकि यह समझने का प्रयास नहीं किया गया कि निर्धन वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की आय निर्धनता रेखा की तुलना में कितनी कम है, साथ ही आय में कमी का वितरण निर्धनों के मध्य किस तरह का है।

भारत में निर्धनता की समस्या– भारतीय संदर्भ में निर्धनता के कारणों की विवेचना की जाय तो इसके बहुआयामी कारक हैं जो कई स्तरों पर प्रभावित करते हैं। माल्थस जैसे अर्थशास्त्री का मानना है कि निर्धनता का कारण वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि समानान्तर दर से बढ़ती है जबकि आबादी गुणोत्तर वृद्धि के अनुसार बढ़ती है। ऐसे में खाद्य पदार्थ की तुलना में तीव्र आबादी का बढ़ना निर्धनता का मुख्य कारण है। जबकि कार्ल मार्क्स का मानना है कि निर्धनता का मुख्य कारण पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों की मजदूरी हड़प कर उनके शोषण करने से है। निर्धनता के संदर्भ में अमर्त्य

सेन का कहना है कि निर्धनता कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं है, बल्कि निर्धनता बहुत सी परिस्थितियों का परिणाम है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देखा जाय तो निर्धनता के बहुआयामी कारण है। जिनमें:– उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, भूमि संसाधनों की कमी, निरक्षरता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, खराब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ, रोजगार की समस्या, आय कम होना, वर्ग विभेद एवं जातिगत ढाँचा, सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़िवादिता, मानसिकता, कुप्रबन्धन, घोटाला एवं भ्रष्टाचार, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, शोषण, दोषपूर्ण विकास नीति, मूल्यवृद्धि एवं स्फीति की समस्या, ऋणग्रस्तता निम्न मजदूरी दर, तकनीकी सेवाओं को अपनाने में कठिनाई एवं प्रदर्शन प्रभाव जैसे अनेक कारण शामिल हैं।

निर्धनता निवारण हेतु किये जाने वाले सरकारी प्रयास एवं कार्यक्रमः– देश में आजादी के समय से ही निर्धनता एक बड़ा मुद्दा रहा है। आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आयी उनकी प्रमुख नीतियों में निर्धनता निवारण का मामला सर्वोपरि रहा है। सरकार द्वारा गठित या अन्य समितियों ने समय–समय पर निर्धनता के परिदृश्य का आकलन कर मापदण्ड निर्धारित किये, परंतु आज भी विश्व में सबसे ज्यादा निर्धन लोग भारत में रहते हैं। गुरूस्वामी और रोनाल्ड जोजेफ गरीबी और भूख के मध्य भेद किया और स्पष्ट किया कि गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है जबकि भूख शारीरिक परिस्थिति है, ऐसे में भूख का कैलोरियों के रूप में परिभाषित करना सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान औपचारिक निर्धनता रेखा की माप कैलोरी उपभोग पर आधारित है। गुरूस्वामी ने यह विश्लेषण किया कि सरकार का यह दावा कि निर्धनता अनुपात जो वर्ष 1973–74 में 54.9 प्रतिशत था वह वर्ष 2004 में कम होकर 25 प्रतिशत हो गया, एक मिथ्या धारणा है। अतः निर्धनता की गत्यात्मक धारणा के लिए बुनायादी आवश्यकताओं का समावेशन अनिवार्य है, और इसे जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग तक सीमित रखना उचित नहीं है।

विशाल भौगोलिक संरचना तथा आबादी वाले देश भारत में प्रत्येक स्तर पर व्यापक विविधताएँ हैं जो इस देश के समाज और विकास प्रक्रिया में परिलक्षित होती है। विगत दशकों में आर्थिक संवृद्धि तथा सरकार की विकास नीतियों से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समेकन में सफलता मिली है, जबकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अंतर और असमानताएँ आज भी मौजूद है। कुछ मामलों में ये असमानताएँ और बढ़ी हैं।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों ने भारत के लिए वर्ष 2015 तक वर्ष 1993 तक की निर्धनता को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया जबकि देश की 30 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने पर विवश है जिसमें निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें मजदूरी करनेवालों की संख्या काफी ज्यादा है। निर्धनता के निवारण हेतु किये जाने वाले प्रयासों में :– ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन कर जमींदारी जैसी व्यवस्था का समूल नाश, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके भूमिहीनों एवं निर्धनों में बांटना, मुद्रास्फीति जैसी समस्या पर रोक, निर्धन वर्ग को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, श्रम तकनीक को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित कर बढ़ावा देना, कमजोर वर्गों को तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर अधिक व्यय, उपभोग की वस्तुओं को कमजोर वर्गों तक सुलभ बनाना एवं जागरूकता आदि जैसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासः– सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति से ही निर्धन एवं सुविधा विहीन वर्ग की संवृद्धि एवं विकास के लिए निरंतर प्रयास करती आ रही है। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता पर सीधा प्रहार करने की नीतियों में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से ही प्रारंभ कर दिये गए थे जिनमें लघु किसान विकास एजेंसी, सीमांत किसान व खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी, सूखा संभाव्यता क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार का पुरजोर जैसे कार्यक्रम चलाए गए परंतु इनका दायरा सीमित था, परंतु देशव्यापी स्तर पर गरीबी के समूल विनाश हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, समग्र आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ट्राईसेम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मनरेगा एवं भारत निर्माण योजना, बाल्मिकी अम्बेडर आवास योजना, इत्यादि कार्यक्रम चलाये गये।

निष्कर्ष एवं सुझाव– नियोजन प्रक्रिया लागू होने के कई दशकों के उपरांत भी देश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या का निर्धन होना निश्चित रूप से खेद का विषय है। नियोजन काल के प्रारंभ से ही यह समझा गया था कि तीव्र आर्थिक विकास के फलस्वरूप निर्धनता स्वतः समाप्त हो जायेगी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिकीकरण के द्वारा रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न होंगे और इससे निर्धनों की आय में वृद्धि होगी परन्तु देखा गया कि विकास की इस नीति का परिणामस्वरूप समाज में असमानता में और वृद्धि हुई है। निर्धनों की निर्धनता और बढ़ती गयी है एवं

सम्पति का संकेन्द्रण कुछ ही हाथों में होने लगा। सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का असर बहुत हद तक गरीबों को प्रभावित नहीं किया है।

गरीबी, भूख एवं बेरोजगारी भारत की राष्ट्रव्यापी समस्या है और ये तीनों ही समस्याएँ किसी भी देश के लिए अपमान एवं सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था की असफलता की सूचक हैं। आज भारत में यदि 25 करोड़ लोगों की प्रतिदिन औसत आय 20 रूपये है और दूसरी ओ 25 लोग प्रतिदिन 5 करोड़ कमाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी आर्थिक नीतियाँ सामंतवादी हैं। नियंत्रित जनसंख्या से ही भूख, भय, बेरोजगारी, बीमारी, एवं हिंसा–मुक्त सभ्य, स्वस्थ सुखी एवं वैभवशाली भारत का निर्माण संभव है।

अतः देश में गरीबी निवारण के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुमुखी योजना की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास और रोजगार के सृजन के साथ–साथ आय एवं सम्पति के न्यायपूर्ण वितरण को भी प्रोत्साहित करे। तभी हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी और असमानता मिटेगी तथा देश का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Govt. of India (2014) Report of Expert Group to Review the Methodology for Measurement of Poverty, Planning Commission, New Delhi
2. Indiabudget.nic.in
3. Ministry of Rural Development, working Pa per.
4.. rojgarsamachar.gov.in
5. Annual Report 2012-13, 2014-15 Ministry of Rural Development Govt. of India.
6. www.rural.nic.in
7. Govt. of India(2009) Report of Expert Group to Review the Methodology of Estimation of Poverty Chaired by S.D. Tendulkar, Planning Commission, New Delhi.
8. Level and pattern of consumer Expenditure, 2004-05 NSS 61st Round (July2004-June 2005) Report No. 508(61/1.0/1) National Sample Survey Organisation Ministry of Sta tistics and Programme Implementation Govt. of India Dec.2006
9. Dandekar V.M. and N.Rath(1971) ' Poverty in India, Economic & Political Weekly, Vol-6, Nos. 182 January 9.
10. Dev Mahendra S(2005), Calorie Norms and Poverty, Economic & Political Weekly, 40(8) : 789-92.
11. Economy Survey 2007-08, 2008-09, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12 & 2012-13, Deptt of Finance Govt. of India.
12. S.K.Mishra & V.K. Puri: Indian Economy Thitieth Revised & Updated Edition 2012 Himalaya Publication House, New Delhi.
13. Dutta & Dundaram: Indian economy, S.Chand and Company Pvt. New Delhi.
14. अमर्त्य सेन–गरीबी और अकाल।

*****